शुक्रवार

खबर के पीछे की खबर...

वर्ष 4 अंक 43 ■ पृष्ठः 12 ■ 20 सितम्बर–26 सितम्बर 2019 ■ नयी दिल्ली ■ ₹ 5

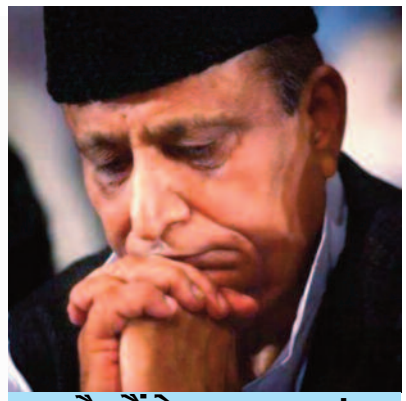

कौन हैं ये आजम खान!

क्या डूब रही है एलआईसी?

गिरीश मालवीय

नयी दिल्ली. भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी क्या डूब रही है. देश के सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में शामिल भारतीय जीवन बीमा निगम रिजर्व बैंक के बाद सरकार के लिए सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी भी है. लेकिन मौजूदा सरकार में निगम का इस्तेमाल दुधारू गाय की तरह होना शुरू हुआ है जिसका नतीजा दो रोज पहले आयी एक खबर है. इसके मुताबिक बीते ढाई महीने में ही निगम को शेयर बाजार में निवेश के लिहाज से सत्तावन हजार करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है. निगम ने जिन कंपनियों में निवेश किया है उनमें से इक्यासी फीसदी के बाजार मूल्य में गिरावट आयी है. निगम ने सबसे अधिक निवेश आईटीसी में कर रखा है. इसके बाद एसबीआई, ओएनजीसी, एलएण्डटी, कोल इण्डिया, एनटीपीसी, इण्डियन आयल और रिलायंस इण्डस्ट्रीज में निवेश है.

बिजनेस स्टैण्डर्ड के मुताबिक जून तिमाही के अंत तक शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में निगम का निवेश मूल्य पाँच सौ तैंतालिस लाख करोड़ रुपये था. अब यह घटकर महज चार सौ छियासी लाख करोड़ रुपये रह गया है. मतलब महज ढाई महीने में निगम के शेयर बाजार में सत्तावन हजार करोड़ रुपये की यह चपत है. रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो मार्च, दो हजार उन्नीस तक निगम ने कुल छब्बीस सौ साठ लाख करोड़ का निवेश किया है जिसमें सरकारी क्षेत्रीय कंपनियों में बाईस सौ साठ लाख करोड़ और निजी क्षेत्र में चार लाख करोड़ रुपये हैं. कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्रीय हालत तो लगातार खराब है अब निजी क्षेत्र भी पिटा जा रहा है.

निगम से ऐसी कई कंपनियों में निवेश कराया गया है जो दिवालिया होने का कगार पर हैं. ऐसी कई कंपनियों की याचिका राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल(एनसीएलटी) ने दिवालियापन की प्रक्रिया(आईबीसी) के तहत स्वीकार कर लिया है.इस सूची में आलोक इण्डस्ट्रीज, एबीजी शिपयार्ड, अम्टेक आटो, मंधाना इण्डस्ट्रीज, जेपी इन्फ्राटेक, ज्योति स्ट्रक्र्स, रेनबो पेपर्स और आर्किड फार्मा जैसे नाम शामिल हैं. सबसे बड़ा नुकसान आईएलएण्डएफएस में झेलना पड़ रहा है. इस कंपनी में निगम की पच्चीस दशमलव तीन चार फीसदी हिस्सेदारी है. आईएलएण्डएफएस समूह पर कुल इक्यान्वे हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है. समूह को धन की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है. यह कंपनी बीते अगस्त के बाद से ही लगभग डिफाल्टर की स्थिति में है.

पिछले साल सरकार के दबाव में आईडीबीआई ने इक्यावन फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बारह हजार छह सौ करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा. यह बैंक देश के बीमार सरकारी बैंकों में सर्वाधिक एनपीए अनुपात वाला बैंक माना जाता है. निगम में देश की अधिकांश जनता की जमा पूंजी है.

अपनी बचत से रुपये निकालकर लोग निगम की पालिसी में लगाते हैं जिसके सहारे उनका और उनके परिवार ...शेष पेज 2 पर

यूपी में हम सुशासन ले आए -योगी

शुक्रवार ब्यूरो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार के ढाई साल पूरे होने पर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरे कार्यकाल में उत्तर-प्रदेश को पहचान की संकट से सरकार ने मुक्त कर दिया है. सिलेसिलेवार अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जोड़ा कि प्रदेश का नकारात्मक चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है. राम के जीवन से जुड़ते हुए योगी ने कहा कि चौदह साल के वनवास के बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब हर क्षेत्र में चुनौती खड़ी थी, लेकिन सरकार ने मुश्किलों को मौकों में बदल दिया. सुशासन लाने में कामयाब हुए.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे. सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के कर्ज को माफ करने का फैसला लिया. इसके तहत छियासी लाख किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ कर दिये गये. सीएम योगी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों उपमुख्यमंत्रियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अभार जताया. कहा कि मोदी के मार्गदर्शन में सरकार एक कुशल टीम की तरह काम कर रही है. उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के प्रति भी अभार जताया और उनके मार्गदर्शन पर खुशी भी.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसान सम्मान योजना के तहत देश भर में सबसे अधिक एक करोड़ सत्तावन लाख किसानों को यूपी सरकार ने फायदा पहुंचाया. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र खोले. सरकार की योजना किसान की लागत कम और मुनाफा अधिक करने की है. अपने गृहनगर पूर्वांचल की खेती का जिक्र करते हुए बताया कि गन्ना की कीमत के रूप में तिहत्तर हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है. पूर्वी उत्तर-प्रदेश में महामारी बन चुके जापानी इंसेफ्लाइटिस पर रोक के लिए सरकारी प्रयासों को भी गिनाया. बताया कि अड़तीस जिलों में दिमागी बुखार प्रभावी था जिसमें पैंसठ प्रतिशत की कमी आयी है. बारह मेडिकल कालेजों से बढकर सरकार एक मेडिकल ...शेष पेज 2 पर

पाकिस्तानियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा

अभयानंद कृष्ण

लखनऊ. भारत के लिए एयर स्पेस पर पाकिस्तान की रोक के जवाब में भारत सरकार ने वैध पासपोर्ट और वीसा होने के बावजूद पाकिस्तान नागरिकों को भारत में सड़क मार्ग से घुसने और निकलने पर रोक लगा दिया है. भारत-नेपाल की खुली सरहद की निगहबानी में जुटे आब्रजन(इमीग्रेशन) कार्यालय को इस बावत स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये गये हैं. जिसके बाद सीमा पर मुस्तैदी बढ़ गयी है. इस वजह से नेपाल ने भी पाकिस्तानियों को आन अराइवल वीसा देने पर रोक लगा दिया है. महराजगंज जनपद के सोनौली स्थित भारतीय आब्रजन कार्यालय के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की .इमीग्रेशन अधिकारी मिथिलेश कुमार तिवारी ने बताया कि बार्डर की सड़क के किसी भी एक्जिट और इंट्री प्वाइंट से पाकिस्तान सहित बारह देशों के नागरिकों के गुजरने पर प्रतिबंध है.

भारत-पाकिस्तान के बीच कड़वे होते रिश्तों में पाकिस्तान के एयर स्पेस से भारतीयों के गुजरने पर प्रतिबंध का पाकिस्तानी ऐलान बीते दिनों सुर्खी बना था. अब भारत ने भी जवाब के रूप में कड़ा कदम उठा लिया है. इसके तहत पाकिस्तानी नागरिक वैध वीसा पर सिर्फ हवाई यात्रा कर सकते हैं उन्हें भारत के भीतर एयरपोर्ट पर उतरने की छूट है, लेकिन भारतीय इमीग्रेशन ने अपने देश में आये पाकिस्तानी नागरिकों को नेपाल जाने के लिए अराइवल वीसा देने पर रोक लगा दिया है. इसी तरह नेपाल से आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भी स्थल मार्ग के प्रयोग की अनुमति नहीं है. यह रोक पाकिस्तान सहित बारह दूसरे देशों के लिए भी है. इनमें ईराक, घाना, सीरिया और कैमरून जैसे अन्य देश हैं. इन बारह देशों को छोड़ शेष मुल्कों के नागरिकों को भारत और नेपाल आने जाने के लिए सड़क मार्ग के प्रयोग की इजाजत है.

सोनौली, भारत-नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार है. इस रास्ते विभिन्न देशों के नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के सहारे आते-जाते हैं. इमीग्रेशन अधिकारी मिथिलेश कुमार तिवारी कहते हैं कि महराजगंज सहित पड़ोस के कई जनपद मुख्यालयों से भारत और नेपाल के बीच खुली सरहद गुजरती है इस लिहाज से सुरक्षा के मद्देनजर गृहमंत्रालय और विभागीय मुख्यालय से समय-समय पर निर्देश जारी होते हैं. इधर पाकिस्तान से रिश्ता बिगड़ने के बाद यह एक नया निर्देश जारी हुआ है जिसे लेकर अधिक मुस्तैदी करनी पड़ रही है.

फारुक अब्दुल्ला आतंकी तो नहीं हैं - तारिगामी

नई दिल्ली. कश्मीर के माकपा नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने केंद्र की भाजपा सरकार के उन दावों पर सवाल उठाए जिनमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से वहां पर एक भी गोली नहीं चली है. माकपा नेता तारिगामी ने कहा कि पाबंदियों के कारण कश्मीर के लोग धीमी गति से मर रहे हैं.वे मीडिया से बात कर रहे थे .

तारिगामी पहले ऐसे कश्मीरी नेता हैं जो हिरासत में रखे जाने के बाद दिल्ली आ सके. इस दौरान उन्होंने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से मुलाकात की. उन्होंने कहा, 'सच्चाई यह है कि धीरे-धीरे मर रहे हैं, घुटन हो रही है वहां.'

वहीं, देश के अन्य हिस्सों से भावनात्मक अपील करते हुए उन्होंने कहा, 'हम भी जीना चाहते हैं, एक कश्मीरी और एक हिंदुस्तानी बोल रहा है यहां. ये मेरी अपील है, हमारी भी सुनें, हमें भी जिंदा रहने का मौका दें.'उन्होंने कहा, राज्य के साथ किसी भी परामर्श के बिना अनुच्छेद 370 को खत्म करना और राज्य का पुनर्गठन करना नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा को दिखाता है. एक औसत कश्मीरी स्वर्ग की मांग नहीं करता है, हम केवल आपके साथ कदम मिलाकर चलने का मौका मांग रहे हैं, हमें भी साथ ले लीजिए.

तारिगामी ने बताया कि उन्होंने कश्मीर में सबसे बुरा समय देखा है लेकिन आज जितना परेशान महसूस किया है उतना कभी नहीं किया. 40 दिनों से अधिक समय से बंद चल रहा है. उन्होंने कहा, 'वे दिल्ली या किसी अन्य शहर में एक सप्ताह तक ऐसा करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि आपका व्यवसाय कैसे चलेगा, आपके स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में और अस्पतालों के बारे में क्या होगा.'

उन्होंने कहा, 'क्या संचार सुविधाओं को ठप्प करके, दैनिक जीवन को अपंग करके, कश्मीरियों की पिटाई करके या जेल में डालकर दिल्ली कश्मीरियों के साथ विश्वास बनाने की कोशिश कर रही है. आज, कश्मीरी राजनेता जेल में हैं, सीमा पार बैठे लोग ताली बजा रहे हैं कि आपने वह कर दिया जो हम नहीं कर सकते थे.'

उन्होंने कहा, 'कश्मीरियों को भारत में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया गया था. कश्मीर के लोगों ने दूसरी तरफ से तानाशाही को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में शामिल होने के लिए. हमें मजबूर नहीं किया गया. कश्मीर और देश के बाकी लोगों ने बहुत मेहनत से जो रिश्ता कायम किया था आज उन पर हमला किया गया है.'

तारिगामी ने कहा, 'न तो मैं विदेशी हूं और न ही डॉ. फारूक अब्दुल्ला या अन्य कश्मीरी नेता आतंकवादी हैं. 4 अगस्त को श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक हुई. बैठक के बाद सभी राजनीतिक दलों की ओर से डॉ. अब्दुल्ला ने मीडिया को जानकारी दी और लोगों से दहशत न फैलाने की अपील की. कुछ ही घंटों बाद आधी रात को मेरे और डॉ. अब्दुल्ला के साथ सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया.'

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म करने को चुनौती देने के लिए अलग से जनहित याचिका दाखिल करेगी.

वहीं इस दौरान वहां मौजूद माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, 'मुख्य मुद्दा लोगों की आजीविका का है. सामान्य जनजीवन को अस्तव्यस्त किए हुए 40 दिन हो चुके हैं. कोई नहीं जानता कि यह कब तक जारी रहेगा. लैंडलाइन सेवाएं अभी भी बाधित थीं. तारिगामी के घर और पार्टी के कई अन्य सहयोगियों के लैंडलाइन काम नहीं कर रहे थे. वहां बहुत से सामानों की कमी है, खासकर अस्पतालों में दवाओं की बहुत कमी थी.'

बता दें कि, 72 वर्षीय तारिगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा के चार बार के विधायक हैं. उन्हें 5 अगस्त से श्रीनगर स्थित उनके आवास पर बिना किसी औपचारिक आदेश के घर में नजरबंद कर दिया गया था.

जब माकपा महासचिव येचुरी को श्रीनगर जाने के दो प्रयासों पर उन्हें हवाईअड्डे से वापस लौटना पड़ा तब येचुरी ने हाईकोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की.29 अगस्त को येचुकी को तारिगामी के घर जाने करने की अनुमति दी गई. इसके बाद तारिगामी के स्वास्थ्य को लेकर येचुरी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें दिल्ली लाया जाए और एम्स में उनका इलाज कराया जाए. इसके बाद 9 सितंबर को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया.

साभार...

पैसे नहीं है अंतर्राष्ट्रीय खिलाडी के पास

प्रयागराज. भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है लेकिन प्रशासनिक मदद की वजह से प्रतिभाएं सिमट कर रह जाती हैं. ऐसी ही एक लड़की है मुस्कान यादव. मुस्कान यादव का सॉफ्ट टेनिस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन होने के बावजूद गोल्डन गर्ल का चेहरा इन दिनों मुरझाया हुआ है. निम्न मध्यमवर्गीय परिवार की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा मुस्कान यादव आर्थिक सहयोग के लिए मंगलवार को डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंची और जब मदद का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो वह फफक कर रो पड़ी.

गोविंदपुर में अप्ट्रॉन चौराहे पर चाय-पान की दुकान लगाने वाले अमर सिंह यादव के छह बच्चों में चौथे नंबर की मुस्कान को सॉफ्ट टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चीन जाना है. एमेच्योर साफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से स्टेट फेडरेशन को भारतीय टीम में चयनित सदस्यों के नाम भेजे गए हैं और कहा गया कि प्रत्येक सदस्य के रहने, खाने-पीने, वीजा आदि के लिए एक लाख 20 हजार रुपये जमा करा दें. मुस्कान को फेडरेशन और सरकार से कोई मदद नहीं मिली तो वह मंगलवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंची.

मुस्कान ने इविवि प्रशासन से आर्थिक सहयोग मांगा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने इस तरह का पहला मामला सामने आया, सो डीएसडब्ल्यू प्रो. हर्ष कुमार ने मुस्कान का आवेदन उच्चाधिकारियों के पास भेज दिया. अब कुलपति ही इस पर कोई निर्णय लेंगे और मुस्कान को 20 सितंबर तक धनराशि जमा करनी है. अगर उसे मदद नहीं मिली तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से वंचित रह जाएगी. यह चैंपियनशिप चीन में 25 अक्तूबर से एक नवंबर तक आयोजित की जानी है.

मुस्कान को 13 से 17 अक्तूबर तक अहमदाबाद में आयोजित होने जा रही पहली साउथ एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के लिए भी यूपी में अकेले चुना गया है. इससे पूर्व मुस्कान ने नवंबर 2018 में कोरिया में आयोजित थर्ड जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में चौथा स्थान स्थान हासिल किया था जबकि इस वर्ष 23 से 31 मार्च तक लखनऊ में आयोजित 16वीं सीनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों में गोल्ड मेडल जीता था.

मुस्कान को आर्थिक सहयोग दिलाने के लिए मंगलवार को पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ऋचा सिंह, निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम छात्रों ने डीएसडब्ल्यू से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि जब छात्रों की फीस में स्पोर्ट्स के नाम पर 50 रुपये, गरीब छात्र के नाम पर दस रुपये लिए जाते हैं तो इस धनराशि से मुस्कान की मदद क्यों नहीं की जा रही है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया जैसी खोखली योजनाएं विश्वविद्यालय एवं स्टेट फेडरेशन के रवैये से अपने मूल रूप में दिख गई.

छात्र ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मदद नहीं करता है तो वे चंदा जुटाएंगे. छात्रों ने चंदा जुटाने का काम भी शुरू कर दिया और तमाम लोग मुस्कान की मदद के लिए आगे भी आए हैं. छात्रों ने अपील की है कि शहर के नागरिक मुस्कान की मदद के लिए आगे आएं.

शुक्रवार
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक और मुद्रक
क्षमता सिंह
के लिए दूसरी मंजिल, बी-146, हरिनगर आश्रम नयी दिल्ली-110014 से प्रकाशित
प्रबंध संपादक
अखंड प्रताप सिंह
संपादक
अंबरीश कुमार
(पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार)
सभी कानूनी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।
संपर्क : 91-8840020355, 979377793
ईमेल: shukrawaardelhi@gmail. com
RNI-DELHIN/2015/65658

पेज 1 का शेष...

क्या डूब रही है ...

का भविष्य सुरक्षित रहता है. मोदी राज में बहुत पहले से ही पैसे की लूट शुरू हो गयी थी लेकिन अब पानी सर तक आ चुका है.

मोदी के नेतृत्व में दूसरा कार्यकाल शुरू तो बड़े जोश-खरोश के साथ हुआ लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनियों के मुश्किल दिन भी साथ ही शुरू हो गये. बीएसएनएल, एचएएल और एयर इण्डिया आर्थिक समस्याओं में पड़ गया अब इस सूची में एक और नाम भारतीय जीवन बीमा निगम का भी शामिल हो गया है.

दरअसल, पिछले ढाई महीने से निगम को शेयर बाजार में हुए निवेश से मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में सत्तावन हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. निगम ने जिन कंपनियों में निवेश किया उनमें से इक्यासी फीसदी के बाजार मूल्य में गिरावट आ गयी. निगम को सरकार के विनिवेश एजेण्डा को पूरा करने के लिए सरकारी कंपनियों के मुक्तिदाता की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. बिजनेस स्टैण्डर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में सार्वजनिक कंपनियों में निगम का निवेश चार गुना हो गया है.

इसके बाद भी मोदी सरकार अगर दावा करती है कि अर्थव्यवस्था में सब कुशल मंगल है तो इस पर विचार किये जाने की जरूरत है. पिछले दिनों देश के रिजर्व बैंक में मोदी सरकार को चौबीस दशमलव आठ अरब डालर यानी लगभग एक सौ छिहत्तर लाख करोड़ रुपये लाभांश और सरप्लस पूंजी को तौर पर देने का फैसला किया है. अब ऐसे हाल में अगर निगम को ही अकेले सत्तावन हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपायी कौन करेगा? कहीं-न-कहीं सरकार को ही इसकी भरपायी करनी होगी और आखिरी धक्का आम आदमी को सहना पड़ेगा. **फोटो साभार**

यूपी में हम...

यूनिवर्सिटी, दो आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और पन्द्रह नए मेडिकल कालेज बना रही है, जबकि चौदह नए प्रस्ताव केन्द्र के पास पड़े हैं. फसलों के न्यूनतम दाम और समर्थन मूल्य भाजपा सरकार ने ही लागू किया.

कानून व्यवस्था को मुस्तैद बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्दांत अपराधी राज्य से बाहर चले गये. डकैती की घटनाओं में चौवन फीसदी कमी आयी. हत्या के मामलों में पन्द्रह, लूट की घटनाओं में तैंतालिस, अपहरण के मामले में तीस और बलवा के मामलों में अड़तीस फीसदी की कमी आयी है.

पूर्वांचल में भूख से मर रहें हैं मुसहर

ठाढ़ीभार (कुशीनगर). उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून व बहुप्रचारित आयुष्मान योजना गरीबों के लिए मजाक बन गयी है. इसका ज्वलंत उदाहरण यूपी का कुशीनगर जिला है, जहां भुखमरी, कुपोषण व बीमारी से मुसहर गरीबों की अकाल मौतें हो रही हैं. इसका खुलासा सीपीआई (एमएल) जांच दल की रिपोर्ट से हुआ है .

केंद्र में मोदी-एक की सरकार ने गरीबों के लिए संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने के बजाए तथाकथित खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून बनाया. इस कानून में, पहले से प्रति परिवार मिल रहे 50 किलो राशन की जगह, पांच किलो प्रति यूनिट कर दिया गया. एक मजदूर के लिए इतना राशन बमुश्किल महीने में केवल पंद्रह दिन के भोजन की गारंटी करता है. गांवों में मनरेगा ठप होने से भूमिहीन मजदूरों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है. इसलिए लोग आसानी से कुपोषण जनित बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. सरकार की आयुष्मान योजना महज प्रचार तक ही सीमित है. कुशीनगर में बीती जुलाई से अब तक (लगभग ढाई माह में) कुपोषण जनित बीमारियों से मुसहर जाति के दस लोगों (पुरूष व महिला, जिनमें कई तो परिवार के मुखिया व एकमात्र कमाऊ सदस्य थे) की हुई मौतें सरकारी ढकोसले की पोल खोलती हैं. मौतों की खबरें आने के बाद भाकपा-माले के तीन सदस्यीय जांच दल ने 10-11 सितंबर 2019 को कुशीनगर का दौरा किया. इस दल में शामिल राज्य कमेटी सदस्य राजेश साहनी, हरीश जायसवाल व कुशीनगर के जिला प्रभारी परमहंस सिंह दुधहीं ब्लाक के ग्राम ठाढ़ीभार पहुंचे. यह वही गांव है जहां मुसहरों की दशा बदलने के नाम पर मुख्यमंत्री बनने के पूर्व योगी ने पदयात्रा की थी.

ठाढ़ीभार ग्राम सभा में 150 से अधिक मुसहर समुदाय से जुड़े परिवार हैं. इस ग्राम सभा में शाहपुर पट्टी के मृतकों के नाम सुदर्शन 38 साल, वैदायी 35, बीपत 30 हैं. इनकी मौत अगस्त मध्य में मामूली बुखार से हुई. राजीटोला के 42 साल के गनेश, रामपुर पट्टी के 17 साल के पंकज, मंगरी 52, ठाढ़ीभार की महिला 55, दुखी 58, बंका 57, तरकुलाही की चंदा 55, एक अन्य जिनकी उम्र 54 साल थी - सबकी मौतें जुलाई से सितंबर के मध्य केवल हल्की बीमारियों से हुई हैं, जिनकी मुख्य वजह कुपोषण है.

इन परिवारों तक न तो प्रशासन की नजर पहुंचती है और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ. उज्जवला गैस योजना में पैसा लेकर चूल्हा कनेक्शन दिया गया. कनेक्शन के बाद किसी ने दुबारा गैस नहीं भरवाया. शाहपुर पट्टी के 90 परिवारों में 45, रामपुर के 80 में से 42, ठाढ़ीभार खास के 12 में से 4, रजही टोला के 46 में से 6 परिवारों को अंत्योदय कार्ड दिया गया है, जिन्हें साल में 2-3 बार ही राशन मिलता है. इन लोगों के घरों में राशन नहीं है, इसलिए भोजन की व्यवस्था अनिश्चित है. गांव में यदा-कदा ही सौ रूपए दैनिक मजदूरी पर काम मिल जाता है.

मनरेगा योजना में साल में 12-15 दिन ही काम दिया गया. पूर्व में जो भी इंदिरा आवास मिले थे वे या तो जर्जर हैं या अधूरे हैं, जिनका उपयोग नहीं हो रहा है. एकाध लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया है. इन 150 से अधिक परिवारों में 100 लोगों को 75-76 में 275 एकड़ भूमि पर पट्टा दिया गया, जिसमें से केवल 7-8 परिवार ही कब्जा ले पाये. इनके पट्टे सड़क से लगे हैं और इन पर पड़ोसी राज्य से आये दबंगों ने कब्जा कर लिया है.

हिंदूवादी संगठन के लोग भी इनको भगाने के लिए दबाव बनाते रहते हैं. अधिकांश लोग खलिहान की जमीन पर झोपड़ी में रहते हैं. आये दिन तहसील प्रशासन भी इन्हें उजाड़ने के लिए प्रताड़ित करता रहता है. शाहपुर पट्टी के प्रधान व लेखपाल ने सत्तर लोगों के लिए आवासीय पट्टे की फाइल तैयार की, तो लेखपाल को हटा दिया गया. राष्ट्रवाद व देशभक्ति की जाप करने वाली मोदी-योगी सरकार और भाजपा-संघ परिवार के लोगों को कुपोषण व गरीबी से हो रही अकाल मौतों को रोकने में देशभक्ति नहीं नज़र आती.

भाकपा-माले ने आगमी 25 व 30 सितंबर को गोरखपुर मंडल की विभिन्न तहसीलों पर मुसहरों की कुपोषण व भुखमरी से हो रही मौतों को रोकने समेत अन्य मांगों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन करने का फैसला किया है. फोटो एक मुसहर परिवार के घर की.

जनचौक डाट काम

एक पत्रकार की डायरी

और मेरी अलग पहचान बन गई

शंभूनाथ शुक्ल

उन तीन पन्नों को पढ़कर कमलेश्वर जी बोले- अरे, इसे बड़ा करो, कहानी बन सकती है. उन्होंने कहा, कि जैसा भोगो, महसूस करो, वही लिखो, यही तो समानांतर कहानी का उद्देश्य है. अब मेरे अन्दर ऊर्जा तो थी ही. मैंने 'भोगे हुए यथार्थ' को लेकर एक कहानी लिख मारी- 'वंश हत्या' यह कहानी दैनिक जागरण के रविवारीय परिशिष्ट में छपी. तब यह परिशिष्ट श्री विजय किशोर मानव देखते थे. उस समय दैनिक जागरण के रविवारीय परिशिष्ट की साहित्यिक समाज में खूब पैठ थी. चूंकि भोगा हुआ यथार्थ था, इसलिए ज़ाहिर है, कहानी के पात्र भी जिंदा थे, मौजूद थे, और वह भी मेरे आस-पास ही. खूब हाय-हाय, किच-किच हुई. लेकिन मेरा नाम चल निकला. कुछ ने इस भोगे हुए यथार्थ को लिपिबद्ध करने के लिए धिक्कारा, अधिकांश ने सराहा. किन्तु कानपुर में मेरा नाम हो गया. इसकी वज़ह थी, अखबार का खूब बिकना और खूब पढ़ा जाना. तब भगेलू से लेकर दीनानाथ राम कलेक्टर तक अखबार जरूर पढ़ते थे, क्योंकि सूचना का और कोई स्रोत नहीं था. मेरी एक अलग पहचान बन गई.

उसी समय दैनिक जागरण ने अपने प्रतिद्वंदी अखबार 'आज' को पटकनी देने के लिए ओपेड पेज को फीचर पेज बनाया. यह एडिट पेज की तरह रोज़ छपता था. इसके प्रभारी थे श्री देवप्रिय अवस्थी. मुझे एक दिन दैनिक जागरण अखबार के तत्कालीन संपादकीय प्रभारी श्री हरिनारायण निगम ने कहा, कि फीचर पेज में युवा, महिला और कालेज कैम्पस के लिए लिखो. कोई विषय उठाओ और अलग-अलग लोगों की राय को समझो, लिखो. उनके फोटो भी होने चाहिए. प्रति लेख 40 रूपये मिलेंगे. यह बहुत मुश्किल काम था. तब किसी महिला को रोक कर उससे बात करना, उसकी फोटो मांगने का मतलब था, पिट जाना. मगर 1977-78 में 40 रूपये बहुत बड़ी रक़म थी. मैं लिखने लगा. मगर जिस किसी दिन कालेज जाकर किसी लड़की से बात करनी होती तथा उससे फोटो मांगते तो मेरा दिल कांपता रहता, कि कहीं पिटाई न हो जाए. तब न तो कैमरा था, न मोबाइल. लेकिन मैं इसे किसी तरह पूरा करने लगा. लड़कियाँ अगले दिन फोटो देतीं. कोई अगले रोज़ आती ही नहीं. तब यह पूछना भी मुश्किल होता. हाथ से लिखता, लगभग रोज़ ही. इस तरह महीने में हज़ार रूपये तो मिल ही जाते.

लेकिन आग जितना ही फैलती है, उतने ही अपने दुश्मन पैदा करती है, यह सिद्धांत मैं भूल गया. नतीजा यह हुआ, कि वे सारे लोग मेरे शत्रु हो गए, जो गर्दिश के दिनों में अपने मित्र थे. एक तरफ तो शहर के एक क्लास में मेरी उठक-बैठक होने लगी, दूसरी तरफ एम-एल के पुराने दोस्तों और साहित्यिक मित्रों के बीच मैं सर्वथा अलोकप्रिय होता गया. शहर के सारे सांसद/विधायक/मेयर और सभासद में पैठ हो गई. कलेक्टर, कप्तान, और तमाम प्रोफेसरों से दोस्ती, किन्तु शत्रु भी उसी तेज़ी से बढ़े. निगम साहब के कान भरे गए, और मुझे काम देना कम किया जाने लगा. तब मैंने राष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं का रुख किया. कलकत्ता से छप रही आनंद बाज़ार पत्रिका समूह के साप्ताहिक 'रविवार' के संपादक श्री एसपी सिंह को एक स्टोरी के लिए पत्र लिखा, उनका जवाब आया- भेज दो. रविवार में मेरी कवर स्टोरी अप्रैल 1978 में प्रकाशित हुई- 'अर्जक संघ- उत्तर प्रदेश का डीएमके!' मुझे रविवार से इस लेख के लिए 200 रूपये मिले. इसके छपते ही फिर से मेरी दैनिक जागरण में डिमांड हुई. तब तक अवस्थी जी वहां से चले गए थे, और मानव जी के पास एडिट पेज एवं ओपेड पेज दोनों आ गए. उनके पास रविवारीय परिशिष्ट भी था, इसलिए उन्होंने एक सहायक की मांग की. पहले के सहायक संतोष तिवारी दिल्ली चले गए थे. मेरी नियुक्ति हो गई. लेकिन पार्ट-टाइम ही. रोजाना दो घंटे आना, और 200 रूपये की फिक्स इनकम. लिखने का अलग. बाहर लिखने की पूरी छूट.

माहौल बदलने के लिए सड़क पर उतरे अखिलेश

राजेंद्र चौधरी

लखनऊ. भाजपा सरकार के प्रदेश की सत्ता में आने के बाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री तथा लोकसभा सदस्य मोहम्मद आजम खां के खिलाफ बदले की भावना से तमाम फर्जी मुकदमें दर्ज कर उन्हें अपमानित करने की साजिशें चल रही है. मोहम्मद आजम खां ने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला, उर्दू गेट बनवाया यह सब भाजपा की नजरों में खटकता हैं. जब भाजपा सरकार के जुल्म की हद हो गई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वयं अन्याय के खिलाफ न्याय और असत्य की जगह सत्य की लड़ाई में हस्तक्षेप करने का इरादा किया.

13 सितम्बर 2019 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लखनऊ से बरेली-रामपुर तक की यात्रा में 10 घंटे से ज्यादा समय लगा. तीन दिन में वे कुल एक हजार कि.मी. यात्रा में आधा दर्जन जनपदों का दौरा किया. 13 सितम्बर से 15 सितम्बर 2019 की इस यात्रा में सैकड़ों जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया. बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता उनके कारवां के साथी थे तो बरेली-रामपुर में स्थानीय लोगों में भी श्री अखिलेश यादव को देखने-सुनने की इतनी उत्सुकता और उत्साह था कि लोग देर रात तक जमे रहे. तड़के भोर में भी लोग उनके विश्राम स्थल पर इकट्ठे हो गये. इससे जाहिर है कि लोग अखिलेश जी को आशाभरी निगाहों से निहार रहे हैं. भाजपा से त्रस्त जनता को दूसरा विकल्प नज़र नहीं आता है. इस यात्रा से प्रदेश की राजनीति में बदलाव का स्पष्ट संकेत है.

लखनऊ के अपने निवास स्थल से निकलते ही उनके जिंदाबाद के नारों के साथ 13 सितम्बर 2019 को जोश में भरे तमाम पार्टी कार्यकर्ता उनके पीछे चल पड़े. कारों का एक बड़ा काफिला साथ चला.

हैरत की बात है कि गड्ढ़ा मुक्त सड़क का दावा करने वाली भाजपा की राज्य सरकार में सीतापुर से बरेली तक सड़क बड़ी बुरी स्थिति में है. श्री अखिलेश यादव ने पूछा पांच वर्ष में केन्द्र सरकार ने इस एन.एच.-1 सड़क पर क्या किया? उन्होंने कहा यहां नौजवान के हाथ में मोबाइल तो है पर हाथ में रोजगार नहीं है. भाजपा राज में जाली नोट, भ्रष्टाचार और काला धन ही चल रहे हैं.

अखिलेश यादव ने आंवला क्षेत्र के पथरी गांव के एक किसान कुंवरपाल मौर्य द्वारा कर्ज न चुकाये जाने के कारण आत्महत्या किए जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती हरदेई मौर्य को 15.09.2019 को बरेली सर्किट हाउस में रूपया 50 हजार तत्काल दिया तथा उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से दो लाख रूपये दिये जाने का आश्वासन दिया. श्री यादव ने सरकार से 20 लाख रूपए दिये जाने की मांग भी की है.

अखिलेश यादव ने लखनऊ से बरेली होते हुए रामपुर और फिर वापसी में सड़क यात्रा में जो दृश्य देखे उससे वे काफी विचलित भी हुए. सीतापुर से बरेली तक की सड़क की दशा तो खराब थी ही पीलीभीत रोड की हालत और खराब दिखाई दी. शाहजहांपुर में भी यहीं हालत रही. इन्हें चारलेन सड़क भी नहीं बनाया गया अखिलेश जी की प्रतिक्रिया थी कि अब तो समाजवादी सरकार बनने पर ही इन सड़कों की दशा सुधर सकेगी. रामपुर में तनिक विश्राम के बाद ही अखिलेश यादव ने विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधिमण्डलों के कार्यकर्ताओं और धर्मगुरूओं से भेंट की. वे सांसद मोहम्मद आजम खां के घर भी गए तथा जौहर विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया. श्री यादव ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री आजम खां के खिलाफ लगाए गए तमाम फर्जी मुकदमों पर रोष जताया और उन्हें न्याय दिलाने में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया. श्री यादव के रामपुर दौरे से समाजवादी कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने में आया और भाजपा सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे अन्याय के प्रतिरोध का जज्बा भी उभरते सामने आया.

(लेखक: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं)

BestSolve
DELIVER COMPLETE SOLUTIONS
For
Digital Print Branding
Electronic Weddings
Radio Outdoor BTL
Rural Marketing Events
Please Contact
Address : Office No.-25, 1st Floor, Uttam Palace, 3 Sapru Marg, Lucknow-226001
Mob: 9935035011, 9793966666
E-mail: bestsolveindia@gmail.com; info@bestsolveindia.com
Website: www.bestsolveindia.com